Recommendations of expert group on delineation of New Hill Areas

*136. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to UQ. 1775 given in the Rajya Sabha on 27-3-1990 and state:

(a) what are the main recommendations of the Export Group on Delineation of New Hill Areas; and

(b) whether the development schemes in regard to Eastern Ghats are being considered by the Planning Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) Sir, the main recommendations of the Expert Group **relate** to evolving of criteria and listing of such areas of the country that conform to the crtieria evolved.

(b) No, Sir.

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी की मांगें

***137. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के संबंध में जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान सरकार से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के समक्ष क्या मांगें रखी थीं ;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गई हैं और यदि शेष किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने सरकार को दिए गए अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित मांगें रखी थीं :

1. अखबारी कागज :

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों को अपनी आबंटन सीमा के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार किसी भी मिल से अपेक्षित स्वदेशी अखबारी कागज उठाने की छूट होनी चाहिए ।

मिलों को मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके तहत स्वदेशी अखबारी कागज की कीमत आयातित अखबारी कागज के जहाज उतरते मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए छोटे और मझौले समाचारपत्रों को दी जाने वाली सहायता जारी रखी जानी चाहिए। अखबारी कागज के आयात का विसंरीकरण किया जाना चाहिए । सरकार को 1990-91 के लिए शेष 60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को रुपया भुगतान क्षेत्र (आर०पी०ए०) से सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी०सी०ए०) में तबदील करने पर विचार करना चाहिए ।

2. सीमा शुल्क :

अखबारी कागज पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए और समाचार पत्र उद्योग को कच्चे माल, उपभोज्य वस्तुओं, अतिरिक्त पुर्जों, हिस्सों, उपकरणों, मशीनरी इत्यादि पर सहायक सीमा शुल्क में वृद्धि से छूट दी जानी चाहिए । समाचारपत्र उद्योग को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नवंबर, 1990 की अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दी जानी चाहिए जिसके तहत वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, घटकों, उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि और अतिरिक्त कल पुर्जों के आयात को निलंबित किया गया है ।